

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में फरवरी, 2023 के महीने के लिए मासिक सारांश।**

**1. जल जीवन मिशन (जेजेएम)**

26.62 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे कुल संख्या 11.24 करोड़ हो गई। महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4,017 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 में कुल जारी राशि 34,628 करोड़ रुपये पहुंच गई।

**2. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण-II (एसबीएम-जी)**

3,64,348 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और 1,657 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1,492 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और 4,847 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर किया गया है। 8,545 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया, जिससे कुल संख्या 1,99,138 पहुंच गई। महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 218.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

**3. प्रगति समीक्षा बैठकें**

(क) माननीय जल शक्ति मंत्री ने 23 फरवरी, 2023 को जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

(ख) सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने मुख्य सचिव, केरल के साथ 6 फरवरी, 2023 को केरल में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की सह-अध्यक्षता की।

(ग) सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 2023-24 के केन्द्रीय बजट भाषण में की गई गोबरधन संबंधी घोषणा के संबंध में दिनांक 10.02.2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उर्वरक तथा आवास और शहरी क्षेत्रों के मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की थी।

(घ) सचिव, डीडीडब्ल्यूएस के नेतृत्व में एक दल ने मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण-II और जल जीवन मिशन दोनों के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए 15 फरवरी, 2023 को तेलंगाना का दौरा किया।

**4. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ**

(क) माननीय प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक में जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न कार्यों का शुभारंभ किया।

(ख) सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 17 फरवरी, 2023 को निविदा पूरी करने और कार्य सौंपने पर विशेष ध्यान देने के साथ जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीसी बैठक की।

(ग) जल जीवन मिशन के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) और पश्चिम बंगाल के एसबीएम-जी के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना को राज्य टीमों के साथ 28 फरवरी, 2023 को अंतिम रूप दिया गया था।

(घ) चालू वित्त वर्ष में जेजेएम के व्यय की समीक्षा के लिए 10 फरवरी, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ङ) एस एंड एमडी (एनजेजेएम) ने 22 फरवरी, 2023 को स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

## 5. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान (एएईटीआई), निमली, अलवर, राजस्थान में 7 से 10 फरवरी, 2023 तक राज्य/जिला अधिकारियों के लिए "ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक का प्रबंधन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 राज्यों के कुल 40 प्रतिभागियों (राज्य सलाहकारों, विशेषज्ञों और बीडीओ) ने भाग लिया।

पंजाब राज्य के लिए ओडीएफ प्लस पर प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण 30 जनवरी से 3 फरवरी, 2023 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में कुल 35 जिला स्तरीय अधिकारियों/अभियंताओं ने भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए ओडीएफ प्लस पर प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण 6-7 फरवरी और 9-10 फरवरी, 2023 को शिमला में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में कुल 80 ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

राजस्थान राज्य के लिए ओडीएफ प्लस पर प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण 13-14 फरवरी, 2023, 15-16 फरवरी, 2023, 17-18 फरवरी, 2023, 23-24 फरवरी, 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में कुल 160 ब्लॉक स्तर अधिकारियों ने भाग लिया।

झारखंड राज्य के लिए ओडीएफ प्लस पर प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण 22-25 फरवरी, 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में कुल 45 जिला/ब्लॉक स्तर अधिकारियों ने भाग लिया।

## 6. मासिक समाचार-पत्र

एसबीएम-जी का मासिक समाचार-पत्र अर्थात "स्वच्छता समाचार" फरवरी, 2023 के महीने के लिए जारी किया गया। यह राज्यों को एसबीएम-जी के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न अभियानों के बारे में अवगत कराएगा। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर सफलता की कहानियों को साझा करने का भी अनुरोध करता है। यह उनके निर्वाचन क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने

में सुविधा प्रदान करेगा। इसे व्यापक और गहन प्रसार के लिए सभी राज्यों के साथ भी साझा किया गया है।

\*\*\*\*\*